Page Three

Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment
Property
Business Opportunity
Vehicles
Announcements
Antiques & Collectables
Barter
Books
Computers
Domain Names
Education
Miscellaneous
Entertainment & Event
Hobbies & Interests
Services
Jewellery & Watches
Music
Obituary
Pets & Animals
Retail
Sales & Bargains
Health & Sports
Travel

Matrimonial (Sunday Only)

अब मात्र रु. 20 प्रति शब्द

कांग्रेस सरकार बनी तो लागू होगी पुरानी पेंशन योजना

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविन्द सिंह कुंजवाल का बयान

वायदा

संवाददाता

देहरादून। चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतारने के बाद अब सियासी दलों की ओर से चुनावी वायदों की बयार बहने लगी है। सत्ता हासिल करने को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा कई लोक लुभावने वायदे किये जा रहे है। पूर्व स्पीकर व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान कर एक बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। ऐसा करके उन्होंने कर्मचारियों और शिक्षकों का दिल जीतने का प्रयास किया है।

कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपने फेसबुक वॉल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को दोबारा बहाल करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही कुंजवाल ने

कहा कि पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। इसी को उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया। लेकिन अब कई राज्यों ने इस पर छूट दी है। उन्होंने कहा कि अगर 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। बताते चले कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर अधिकारी कर्मचारी लंबे समय से संघर्षरत है। यही नहीं, कर्मचारियों का कहना है कि इस बार वह उन्हीं को वोट देंगे, जो पुरानी पेंशन को बहाल करेगा। जिसको लेकर इन दिनों सोशल मीडिया में भी कर्मचारियों का कैम्पैन जोर शोर से चल रहा है।

राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ० डी० सी० पसबोला, प्रान्तीय महासचिव सीताराम पोखरियाल सहित समस्त एनपीएस कार्मिकों ने पूर्व स्पीकर व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल की पुरानी पेंशन की बहाली के ऐलान का स्वागत किया है एवं अन्य राजनीतिक दलों से भी पुरानी पेंशन बहाली के सम्बन्ध में सहयोग देने की अपील की है।

क्या है पुरानी पेंशन योजना

केंद्र सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद के नियुक्तियों के लिए पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था और नई पेंशन योजना लागू की गई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यह फैसला लिया गया था। तब उत्तराखंड में एन डी तिवारी की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। पिछले कुछ सालों से कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना का विरोध करना शुरू कर दिया।

न्यूज डायरी

नैनीताल जिले की छह सीटों पर आठ ने छोड़ा मैदान, 64 के बीच होगी टक्कर

संवाददाता हल्द्वानी। नैनीताल जिले से आठ प्रत्याशियों ने विधानसभा चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। कालाढूंगी सीट से भाजपा के गजराज बिष्ट व एक निर्दल ने मैदान छोड़ दिया। हल्द्वानी से आम आदमी पार्टी की डमी प्रत्याशी स्मृति टिक्कू, नैनीताल से भुववन आर्य व मीनाक्षी, भीमताल से नंदाबल्लभ, रामनगर से गौरव रावत ने नाम वापस ले लिया है। रामनगर से एक निर्दल भी चुनावी समर से बाहर हो गया। जिले की छह सीटों से 64 प्रत्याशी चुनाव मैदान में जमे हैं। इनमें 20 निर्दल हैं। मैदान में उतरे प्रत्याशियों में छह महिलाएं हैं। निर्वाचन आयोग ने सोमवार नाम वापसी का दिन तय किया था। लालकुआं सीट से किसी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। ऐसे में यहां सबसे अधिक 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हैं।

चार धाम, चार काम को लेकर जनता के बीच जा रही कांग्रेस

संवाददाता अल्मोड़ा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अविजीत ने कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि चार धाम, चार काम को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर चार लाख नौकरी, 500 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर के दाम करना, न्याय योजना के तहत पांच लाख गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देना और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर, दालें, खाद्यान्न, पेट्रोल डीजल सहित दैनिक उपभोग की सभी वस्तुओं के मूल्य आसमान पहुंच गये हैं। गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के सामने अपने भरण पोषण की कठिन समस्या उत्पन्न हो गई है। भाजपा राज में थोक महंगाई 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।

भाजपा ने सतपुली में खोला चुनाव कार्यालय

संवाददाता देहरादून/सतपुली। विधानसभा चौबट्टाखाल के नगर पंचायत सतपुली में भाजपा ने सोमवार को विधिवत सबसे पहले चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर कोविड नियमों का पालन करते हुए चुनाव प्रचार की शुरूआत की। विधानसभा चौबट्टाखाल के नगर पंचायत सतपुली में पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने सोमवार को सबसे पहले भाजपा चुनाव कार्यालय में पूजन कर व रिबन काटकर चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव कार्यालय खोलने की शुभकामना देते हुए कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को दूसरी बार विधानसभा चौबट्टाखाल से रिकॉर्ड मतों से विजय बनाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को एक कमल भेंट करना है।

15 फरवरी से फिर शुरू होगा 'स्वस्थ्य घर–स्वस्थ्य उत्तराखंड अभियान'

संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड के जाने–माने सीनियर फिजीशियन व कॉडियोलाटिस्ट डॉ एसडी जोशी ने देहरादून स्थित अपने शंकर क्लीनिक में प्रेसवार्ता का आयोजन किया। प्रेसवार्ता में डॉ एसडी जोशी ने अपनी साल 2022 की कार्ययोजनओं रखकर बताया कि एक बार फिर "स्वस्थ्य घर–स्वस्थ्य उत्तराखंड अभियान" शुरू करने जा रहे हैं। इस अभियान की शुरूआत चमोली जनपद के दुर्गम गांव से होगी।

डॉ जोशी ने बताया उनके इस अभियान में विचार एक नई सोच संस्था प्रमुख सहयोगी की भूमिका में रहेगी। संस्था निशुल्क दवाईयों के साथ ही कोरोना जागरूकता को लेकर मास्क व सेनेटाइजर भी उपलब्ध करायेगी। इस दौरान प्रेसवर्ता में डॉ जोशी के साथ विचार एक नई सोच संस्था के संचालक राकेश बिजल्वाण मौजूद रहे। पत्रकारवार्ता में डॉ एसडी जोशी के क्लीनिक के टीम के सदस्य दीपक जुगराण, कपिल थापा, हिमानी, प्रदीप चमोली, मोहन पुरोहित व अभिषेक ममगई मौजूद रहे।

सीनियर फिजीशियन व कॉडियोलाटिस्ट डॉ एसडी जोशी ने बताया कि एक बार फिर आगामी 15 फरवरी से वह "स्वस्थ्य घर–स्वस्थ्य उत्तराखंड" अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस बार उनका प्रयास है कि सीमांत गांवों में पहुंचकर निशुल्क हैल्थ कैंप लगाए जायें। उनकी प्राथमिकता में चमोली, पिथौरागढ़ व उधमसिंहनगर जनपद हैं। वह अलग–अलग विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लेकर सीमांत गांवों में जायेंगे।

पावन स्नान पर कोई पाबंदी नहीं, कम संख्या में पहुंचे श्रद्धालु

संवाददाता देहरादून। सोमवार को सोमवती अमावस्या और कल एक फरवरी को मौनी अमावस्या का स्नान पर्व था। इस बार जिला प्रशासन ने हरकी पैड़ी समेत किसी भी गंगा घाट पर स्नान के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई। सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार के घाटों पर अपेक्षाकृत कम भीड़ नजर आई। इस कारण तीर्थनगर में पड़ रही भीषण ठंड माना जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद नारायणी शिला में पितरों का पूजन भी किया। बॉर्डर पर नियमित चेकिंग चल रही है। बॉर्डर पर दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाने या 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। मालूम हो कि मकर संक्रांति पर्व पर हरकी पैड़ी समेत प्रमुख गंगा घाटों को सील कर दिया गया था। स्थानीय लोगों को कुछ ही घाटों पर डुबकी लगाने की छूट दी गई थी।

पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का दावा, डैमेज कंट्रोल में सफल हुई भाजपा

संवाददाता देहरादून। पूर्व केंद्रीय मंत्री व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने यह दावा किया है कि भाजपा डैमेज कंट्रोल में सफल हुई है। गौरतलब है कि सोमवार को उत्तराखंड में नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। इस क्रम में पार्टियों द्वारा बागी नेताओं को मनाने का दौर जारी रहा।

सभी नामांकन करने वाले हमारे परिवार के सदस्यः सोमवार को हरिद्वार सांसद निशंक ने कहा कि डोईवाला में भाजपा से बागी होकर नामांकन करने वाले सौरभ थपलियाल, सुभाष भट्ट, राहुल पंवार ने नाम वापस ले लिया है। हरिद्वार में जय भगवान, रुड़की में टेक बहादुर और नितिन शर्मा

मान गए हैं। कहा कि सभी नामांकन करने वाले हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम उन्हें भी मना लेंगे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा डैमेज कंट्रोल में सफल हुई है।

भाजपा 60 से अधिक सीटें लाकर लहराएगी परचमः रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में 60 से अधिक सीटें लाकर भाजपा अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हर तरफ विकास की लहर चल रही है। इससे साफ हो चुका है कि भाजपा की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो विदेशी ताकतों से लड़ने का काम कर सकती है।

स्विट्जरलैंड से पहुंची एक्सपर्ट टीम ने किया जमरानी का अध्ययन

संवाददाता हल्द्वानी। सात दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी होने के बाद स्विट्जरलैंड से पहुंची चार सदस्यीय टीम जमरानी का सर्वे करेगी। सोमवार को टीम ने भैतिक निरीक्षण किया। सुरक्षा, संसाधनों की उपलब्धता, बांध निर्माण से होने वाले अलग–अलग फायदों के अलावा कई बिंदुओं पर यह एक्सपर्ट टीम चार दिन तक अध्ययन करेंगे। एडीबी के निर्देश पर पहुंचे विशेषज्ञों के हर सुझाव को परियोजना के प्रस्ताव में शामिल करना होगा। जमरानी बांध निर्माण की कवायद 1975 में शुरू हुई थी। पुरानी दो डीपीआर बजट के चक्कर में अटक गई थी। उत्तराखंड बनने के बाद सर्वे और प्रस्ताव बनाने के काम फिर से शुरू हुए। पिछले दो साल में एडीबी और जमरानी परियोजना के अधिकारियों ने सामंजस्य बनाकर सर्वे से जुड़े अलग–अलग कामों को रफ्तार से किया। शासन के निर्देश पर प्रस्तावित बांध व आसपास के क्षेत्र की 400 हेक्टेयर जमीन पर धारा 11 लागू हो चुकी है।